भारत सरकार

रेल मंत्रालय

लोक सभा

25.03.2026 के

अतारांकित प्रश्न सं. 5322 का उत्तर

रेल भूमि विकास प्राधिकरण की परियोजनाएं

5322. श्री कुंदुरु रघुवीर:

क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) देशभर में रेलवे की भूमि के वाणिज्यिक विकास और मुद्रीकरण के लिए रेल भूमि विकास प्राधिकरण (आरएलडीए) द्वारा उसकी स्थापना के बाद से शुरू की गई परियोजनाओं की कुल संख्या कितनी है और उनके स्थानों का ब्यौरा क्या है;

(ख) वर्तमान में निष्पादित की जा रही या अभी शुरू की जाने वाली परियोजनाओं सहित अब तक पूरी हो चुकी/चालू की गई उक्त परियोजनाओं की संख्या कितनी है;

(ग) क्या सरकार ने आरएलडीए की परियोजनाओं के कार्यान्वयन में विलंब और उक्त विलंब के कारण रेलवे की कितनी भूमि अप्रयुक्त रही या कम उपयोग में लाई गई, का आकलन किया है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) विगत पांच वर्षों के दौरान आरएलडीए की परियोजनाओं से प्राप्त कुल राजस्व का ब्यौरा क्या है और रेलवे की भू-संपत्तियों के समयबद्ध विकास के माध्यम से प्राप्त की जा सकने वाली अनुमानित राजस्व क्षमता कितनी है?

उत्तर

रेल, सूचना और प्रसारण एवं इलेक्ट्रोनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री

(श्री अश्विनी वैष्णव)

(क) से (घ): रेल मंत्रालय द्वारा रेलवे की खाली भूमि, जिसकी रेलों को अपनी तात्कालिक परिचालनिक आवश्यकताओं के लिए आवश्यक नहीं है, रेल भूमि विकास प्राधिकरण को सौंप दी जाती है। इस भूमि का जहां कहीं व्यवहार्य हो, वाणिज्यिक विकास के लिए उपयोग किया जाता है ताकि गैर-किराया राजस्व प्रयोजनार्थ अतिरिक्त वित्त संसाधनों को एकत्रित किया जा सके।

अब तक रेलवे की लगभग 1,308 हेक्टेयर भूमि रेल भूमि विकास प्राधिकरण (आरएलडीए) को वाणिज्यिक विकास और कॉलोनी पुनर्विकास आदि के लिए सौंपी गई है। इस 1,308 हेक्टेयर भूमि में से लगभग 220 हेक्टेयर भूमि को 20,655 करोड़ रुपए की कुल राशि पर वाणिज्यिक विकास के लिए पट्टे पर दिया गया है। अब तक (फरवरी 2026 तक) रेल भूमि विकास प्राधिकरण ने लगभग 7,053 करोड़ रुपए का राजस्व अर्जित किया है।

इसके अलावा, रेल भूमि को सफलतापूर्वक और समयानुसार पट्टाकृत करना कई कारकों जैसे कि भूमि दस्तावेजों की उपलब्धता, अन्य विभागों से मंजूरी आदि पर निर्भर करता है।

******